बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 53 ● नई दिल्ली ● वीरवार 04 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

गैस मास्क पहनकर संसद परिसर पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, बोले- फरवरी आते ही भूल जाते हैं लोग

नई दिल्ली । संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली-एनसीआर के जानलेवा वायु प्रदूषण के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध जताकर सबका ध्यान खींचा। वह प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाने के लिए गैस मास्क पहनकर संसद परिसर पहुंचे। नवंबर आते-आते दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की समस्या शुरू हो जाती है। तब सभी इस पर चिंता व्यक्त करते हैं लेकिन फरवरी आते-आते इसे भूल जाते हैं। मीडियाकर्मियों द्वारा गैस मास्क पहनने का कारण पूछे जाने पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा और दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है।

एमसीडी उपचुनाव के नतीजों पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान, यह कड़ी मेहनत का मजबूत प्रमाण है

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा 12 में से सात सीटें जीतने पर राष्ट्रीय राजधानी की जनता की सराहना की है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने भगवा पार्टी के प्रदर्शन का श्रेय भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया और विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य आशीर्वाद देने के लिए दिल्लीवासियों का हार्दिक धन्यवाद। यह जीत हमारे मेहनती कार्यकर्ताओं और संगठन की अथक मेहनत, समर्पण और सामूहिक शक्ति का एक सशक्त प्रमाण है। रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि उपचुनाव में विजयी सभी भाजपा उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई। हमारी सरकार दिल्ली के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और निरंतर काम कर रही है। हालाँकि, इस उपचुनाव में भाजपा को दो सीटों का नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले चुनाव में उसने इन 12 सीटों में से नौ पर जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी ने तीन सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने भी एक सीट जीतकर अपना खाता खोला। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (एआईएफबी) ने भी एक सीट जीती। वहीं, चनावी नतीजों पर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि निगम उपचुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारा और दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से ये साफ़ कर दिया है कि दिल्ली का जनसमर्थन लगातार आप की तरफ़ मज़बूत हो रहा है। सिर्फ़ 10 महीनों में ही जनता का विश्वास एक बार फिर तेज़ी से आम आदमी पार्टी की ओर लौट रहा है। दिल्ली बहुत जल्द वापस सकारात्मक राजनीति और अच्छे कामों की तरफ़ लौट रही है। इस बीच, आप खेमे से राजन अरोड़ा, अनिल और राम स्वरूप कनौजिया ने वार्ड 139 नारायणा, वार्ड 35 मुंडका और वार्ड 164 दक्षिण पुरी से जीत हासिल की। दक्षिण पुरी एकमात्र अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है जहाँ चुनाव हुए। इस बीच, एआईएफबी के मोहम्मद इमरान और कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने क्रमशः वार्ड 76 चांदनी महल और 163 संगम विहार-ए से जीत हासिल की। चांदनी चौक से विजयी हुए सुमन कुमार गुप्ता ने ट्रैफिक जाम, बिजली और पानी से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान का वादा किया।

एमसीडी उपचुनाव के बाद नतीजों पर बोले केजरीवाल, जनता का भरोसा आपकी ओर बढ़ा

नई दिल्ली ।

भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उपचुनावों में बड़ी जीत हासिल की, जिसमें 12 वार्डों में से 7 पर जीत हासिल की, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सभी 5 वार्ड शामिल हैं, जहां 30 नवंबर को मतदान हुआ था।

आम आदमी पार्टी (आप) ने 3 सीटें, जबकि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (एआईएफबी) और कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती। हालांकि, परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद, आप ने चुनावी कदाचार का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा द्वारा रणनीति अपनाने के बाद भी उनकी सीटों की संख्या 9 से घटकर 7 हो गई। वहीं, चनावी नतीजों पर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि निगम उपचुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारा और दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से ये साफ़ कर दिया है कि दिल्ली का जनसमर्थन लगातार आप की तरफ़ मज़बूत हो रहा है। सिर्फ़ 10 महीनों में ही जनता का विश्वास एक बार फिर तेज़ी से आम आदमी पार्टी की ओर लौट रहा है। दिल्ली बहुत जल्द वापस सकारात्मक राजनीति और अच्छे कामों की तरफ़ लौट रही है। इस बीच, आप खेमे से राजन अरोड़ा, अनिल और राम स्वरूप कनौजिया ने वार्ड 139 नारायणा, वार्ड 35 मुंडका और वार्ड 164 दक्षिण पुरी से जीत हासिल की। दक्षिण पुरी एकमात्र अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है जहाँ चुनाव हुए। इस बीच, एआईएफबी के मोहम्मद इमरान और कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने क्रमशः वार्ड 76 चांदनी महल और 163 संगम विहार-ए से जीत हासिल की। चांदनी चौक से विजयी हुए सुमन कुमार गुप्ता ने ट्रैफिक जाम, बिजली और पानी से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान का वादा किया। उन्होंने एएनआई को बताया कि मैं ट्रैफिक जाम, सीवर, बिजली और पानी से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान के लिए काम करूँगा। मुख्यमंत्री ने चांदनी चौक के लिए 100 करोड़ रुपये देने का वादा किया था और हम इस फंड का इस्तेमाल इलाके के विकास और चांदनी चौक के गौरव को बहाल करने के लिए करेंगे। आप के राम स्वरूप ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का आभार व्यक्त किया।

लोकभवन नामकरण पर राज्यसभा में हंगामा- खड़गे-नड्डा के बीच तीखी नोकझोंक, विपक्षी सांसदों का शोर

नई दिल्ली । बुधवार को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति सीपी राधाकृष्णन के बीच तीखी बहस हुई। उच्च सदन में रायपाल के आवास का नाम बदलकर लोकभवन करने पर चर्चा के लिए सहमति बनने के बाद यह बहस शुरू हुई। खड़गे ने सभापति राधाकृष्णन से कहा कि हर चीज़ इस विषय से जुड़ी है और आपके (रायसभा अध्यक्ष) कार्यालय में इस विषय पर चर्चा हुई थी। उसके बाद सिर्फ़ उन्होंने (डोला सेन) ही बात की। सदन के नेता हस्तक्षेप नहीं कर सकते और यह नहीं कह सकते कि सब कुछ असंसदीय है, आप हटाएँ। नेता कह रहे हैं, नेता बुलडोज़र चला रहे हैं। जेपी नड्डा द्वारा चर्चा से असंबंधित किसी भी बात को हटाने के आह्वान पर सवाल उठाते हुए, खड़गे ने रायसभा के सभापति से पूछा, क्या हम संसदीय लोकतंत्र के अनुसार (सदन को) नहीं चलाना चाहते? सभी रिकॉर्ड, उन्हें सुरक्षित रखें, एक भी शब्द नहीं हटाया जाना चाहिए। नड्डा ने भी खड़गे के आरोप का जवाब देते हुए सभापति राधाकृष्णन से पूछा कि मुझे आपकी सुरक्षा चाहिए महोदय, मैंने कभी बुलडोज़र नहीं चलाया, मैंने केवल इतना कहा है कि जो भी विषय से संबंधित है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और जो संबंधित नहीं है, आप कृपया उसकी जाँच कर सकते हैं। यह बहस तब हुई जब टीएमसी सांसद डोला सेन ने इस मुद्दे पर बात की और भाजपा पर तानाशाही चलाने का आरोप लगाया, जिसे अंततः जनता उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने दावा किया कि राजभवन, जो अब लोकभवन है, का नाम बदलने से पहले राज्य सरकारों से सलाह नहीं ली गई। टीएमसी सांसद डोला सेन ने अपने भाषण में कहा, (लोकभवन) का खर्च राय सरकार कई वर्षों से उठा रही है, लेकिन राय विधानसभा को इन अधिसूचनाओं (नाम परिवर्तन संबंधी) की जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से राय सरकार से सलाह ली जानी चाहिए। यह न केवल संघवाद पर हमला है... बल्कि वास्तव में राजभवन को एक समानांतर सरकार चलाने और उन्हें भाजपा के विस्तारित पार्टी पदाधिकारियों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने पूछा, एक बड़ी साजिश के तहत, बंगाल में गृह मंत्रालय के आदेश को लागू कर दिया गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लोगों की क्या स्थिति है? उन्होंने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल का बकाया न चुकाने का आरोप भी लगाया, जिसमें मनरेगा के लिए 43 हज़ार करोड़ रुपये, चक्रवातों के लिए 42,600 करोड़ रुपये और ग्रामीण आवास योजना के लिए 24,200 करोड़ रुपये शामिल हैं। टीएमसी सांसद के भाषण के बाद सदन के नेता और भाजपा सांसद जेपी नड्डा ने सभापति से अनुरोध किया कि वे डोला सेन के शब्दों की जांच करें और जो भी बातें चर्चा से संबंधित न हों उन्हें रिकॉर्ड से हटा दें।

रणनीतिक बदलाव! विपक्षी दल अब चुनाव सुधारों पर चर्चा में सरकार को देंगे सीधी टक्कर

नई दिल्ली ।

तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि विपक्षी दलों ने संसदीय लोकतंत्र की भावना के अनुरूप चुनाव सुधारों पर चर्चा के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अपने रुख में एक रणनीतिक बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने और चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान सरकार को घेरेंगे। विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा पर ज़ोर दे रहे थे, जो चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है। डेरेक ओब्रायन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक ज़िम्मेदार विपक्ष ने संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। हम विनम्र और मिलनसार रहे हैं, भले ही हम एक ऐसी सरकार के खिलाफ हैं जो संसद का मज़ाक उड़ाती है। हाँ, SIR पर चर्चा सर्वोच्च प्राथमिकता थी और है (लोग मर रहे हैं)। हालाँकि, संसदीय लोकतंत्र की भावना के अनुरूप, हमने समय के बारे में सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और एक रणनीतिक बदलाव किया। हम दोनों बहसों में सरकार को घेरेंगे। लाओ। इससे पहले, विपक्षी दलों ने चुनाव सुधारों पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर रायसभा से बहिर्गमन किया। उन्होंने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि सरकार ने चुनाव सुधारों पर चर्चा की मांग स्वीकार कर ली है, लेकिन विपक्षी दलों को समयसीमा पर ज़ोर नहीं देना चाहिए। सरकार चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष को समयसीमा पर ज़ोर नहीं देना चाहिए। रिजिजू ने इससे पहले दिन में कहा था कि वह विपक्ष की मांग पर सरकार का रुख स्पष्ट करेंगे। हंगामे के बीच उन्होंने कहा, हमने पहले दिन से ही कहा था कि हमें शांत मन से बहस करनी चाहिए। कल हमने विरोध का विरोध किया था। आज मैं फिर से इसका (विपक्षी नारेबाजी का) विरोध करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि देश में कई मुद्दे हैं, मैं किसी भी मुद्दे को दूसरे से छोटा नहीं मानता, लेकिन संसद नियमों के अनुसार काम करती है, आप अन्य मुद्दों को दबा नहीं सकते।

ईमेल से दिल्ली विवि के दो कॉलेजों को बम से उड़ाने की चेतावनी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

नई दिल्ली । दिल्ली विश्वविद्यालय के दो कॉलेजों को बुधवार सुबह ईमेल के ज़रिए बम की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया और बम निरोधक दल (बीडीडीटी) और पुलिस को तैनात किया गया। ऐसे ही ईमेल की श्रृंखला में सबसे ताज़ा ईमेल सुबह लगभग 1.59 बजे रामजस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज को भेजा गया। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बंठिया ने बताया कि रामजस कॉलेज के प्राचार्य ने सुबह-सुबह धमकी की सूचना दी, जिसके बाद बीडीडीटी और स्थानीय पुलिस ने परिसर में तोड़फोड़-रोधी जाँच शुरू कर दी। देशबंधु कॉलेज में भी इसी तरह की जाँच की गई। अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस ने बताया कि धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की पहचान अभी नहीं हो पाई है। रामजस कॉलेज के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने सुबह करीब 10 बजे मेल चेक किया और तुरंत कर्मचारियों और छात्रों को परिसर खाली करने को कहा। छात्रों को परिसर से बाहर निकाला गया और पुलिस को बुलाया गया। रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल अजय अरोड़ा ने बताया कि प्रैक्टिकल परीक्षाएँ बुधवार को होनी थीं। लेकिन जैसे ही हमें बम की धमकी मिली, हमने तुरंत कॉलेज खाली कर दिया और छात्रों को घर वापस जाने को कहा। देशबंधु कॉलेज के प्रिंसिपल राजेंद्र पांडे ने कहा कि वे बम निरोधक दस्ते की अनुमति का इंतज़ार कर रहे थे। 20 नवंबर को दिल्ली के पाँच स्कूलों को बम विस्फोटों की चेतावनी वाले ईमेल मिले, जिसके बाद स्कूलों को खाली कराया गया और तलाशी ली गई, लेकिन बाद में इन धमकियों को अफवाह घोषित कर दिया गया। दो दिन पहले, दिल्ली की चार ज़िला अदालतों और केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल द्वारा संचालित दो स्कूलों को भी इसी तरह की धमकियाँ मिली थीं। साकेत, पटियाला हाउस, रोहिणी और द्वारका अदालतों में सुनवाई रोक दी गई और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। 28 अक्टूबर को दिल्ली के 200 से अधिक स्कूलों को ई-मेल के माध्यम से बम की धमकी मिली, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया, तथा बाद में धमकी को अफवाह घोषित कर दिया गया।

ख़तरे की घंटी- साम्राज्यवादी देशों का बढ़ता सैन्यीकरण

प्रभात पटनायक

इसी साल जून में हुए नाटो के शिखर सम्मेलन की घोषणा में, सभी नाटो देशों ने इसके लिए सहमति दी है कि 2035 तक अपने सैन्य खर्चों को बढ़ाकर, अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5 फीसद के बराबर कर देंगे। 2024 में यह अनुपात 3.5 फीसद था और यूरोपीय यूनियन में तो यह अनुपात 1.9 फीसद ही था। इसका अर्थ यह है कि सैन्य खर्चों में खासी भारी बढ़ोतरी की जाएगी और यूरोपीय यूनियन में तो खासतौर पर भारी बढ़ोतरी की जाएगी। इसी प्रकार जापान भी, जिसने विश्व युद्ध के बाद एक शांतिवादी नीति के लिए वचनबद्धता स्वीकार की थी और अपने सैन्य खर्च पर जीडीपी के 1 फीसद की अधिकतम सीमा लागू की थी, वह भी समय के साथ इस अनुपात को बढ़ाता रहा है। इस समय यह जीडीपी का 1.8 फीसद सैन्य मदों में खर्च करता है। लेकिन, उसकी नयी प्रधानमंत्री सनेई ताकाइची ने इस सिलसिले में अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद, अपने पहले ही भाषण में उन्होंने एलान किया है कि इस वित्त वर्ष के आखिर तक, यानी 2026 के मार्च तक इस अनुपात को बढ़ाकर 2 फीसद कर दिया जाएगा। इस तरह, हम सभी साम्राज्यवादी देशों में सैन्यीकरण की गति में उल्लेखनीय तेजी देख रहे हैं और यह कुल मिलाकर एक नया घटनाविकास है। सैन्यीकरण में इस तेजी को उचित ठहराने के लिए, हर प्रकार के खतरों की और खासतौर पर रूसी खतरे की दुहाई दी जा रही है। साम्राज्यवादी प्रचार मशीन रूसी विस्तारवाद का भूत खड़ा करने जुटी हुई है, यूक्रेन पर चढ़ाई को कथित रूस में इसका पहला कदम बताया जा रहा है। लेकिन, सच्चाई यह है कि नाटो ही है जिसने मिखाइल गोर्बाचेव को क्लिंटन प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था उसके खिलाफ जाकर, अपनी सदस्यता का विस्तार किया है, जिससे रूसी सीमाओं तक के देशों को अपने साथ शामिल किया जा सके और इस प्रकार रूस को करीब-करीब घेरा जा सके। तथ्य यह है कि रूस ने इस विस्तार को भी बर्दाश्त कर लिया था और इस पर अपना विरोध तभी जताया था जब नाटो ने यूक्रेन को भी अपने साथ शामिल करना चाहा था। तथ्य यह भी है कि यूक्रेन और रूस के बीच मिन्स्क समझौते के रूप में किसी सैन्य कार्रवाई की नौबत ही नहीं आयी होती, लेकिन पश्चिमी हस्तक्षेप ने उसे विफल करा दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, बोरिस जानसन खास इसके लिए उड़कर कियव पहुंचे थे, ताकि यूक्रेन को उस समझौते से मुकरने के लिए तैयार कर सकें। ये सभी तथ्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि इस मामले में विस्तारवादी सत्ता कौन सी है। रूस का हौवा तो सिर्फ इसलिए खड़ा किया जा रहा है ताकि पश्चिमी साम्राज्यवादी सैन्यीकरण में तेजी को उचित ठहराया जा सके। बहरहाल, यूरोप में इस प्रचार की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि कोई भी अगर इस सच्चाई की ओर इशारा करता है, उसे रूसी एजेंट और पुतिन का पैरोकार करार दे दिया जाता है। जर्मनी की वामपंथी नेता सहरा वेगनेक्नेत, जिन्होंने डाइ लिंके से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनायी थी, जर्मन मीडिया में सिर्फ इसलिए हमलों का निशाना बनायी गयीं कि उन्होंने तथाकथित रूसी खतरे के खोखलेपन को इंगित किया था और यूरोपीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के एक साधन के रूप में, रूस के साथ सहयोग की वकालत की थी। वास्तव में रूस के प्रति यूरोप का रुख काफी अजीबो-गरीब लगता है। पश्चिमी ताकतों ने रूस पर जो इकतरफा पाबंदियां थोपी हैं, उनका नतीजा यह हुआ है कि यूरोप को मजबूर होकर रूस से ऊर्जा आयात की जगह पर, जिन पर तब अब तक निर्भर रहा था, कहीं महंगी अमरीकी ऊर्जा आयात को गले लगाना पड़ रहा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जर्मनी में और अन्यत्र भी जीवन-यापन का खर्चा बढ़ गया है और इसलिए, मेहनतकश वर्गों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। और इसने उत्पादन लागतें भी बढ़ा दी हैं, जिससे जर्मन माल गैर-प्रतिस्पर्द्धी हो रहे हैं। यह जर्मनी में निर्माताओं को हतोत्साहित कर रहा है और वहां ''निरउद्योगीकरण'' की प्रक्रिया का कारण बन रहा है। बेशक, अमरीका द्वारा यूरोप पर दबाव डाला जा रहा है जिससे वह अपनी ऊर्जा के लिए, वहां एक बाजार सुनिश्चित कर सके। लेकिन, इकतरफा पाबंदियों के मामले में यूरोप ने जिस तरह से अमरीका के सामने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है और इसके लिए वह खुद अपने हितों की भी बलि देने के लिए तैयार है, वह बेशक काफी हैरान करने वाला है।

इस परिघटना का एक स्वतःस्पष्ट कारण तो वर्तमान यूरोपीय नेतृत्व की प्रकृति में ही निहित है। इस नेतृत्व का ज्यादातर हिस्सा कार्पोरेट से और खासतौर पर अमरीकी कार्पोरेट से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर जर्मनी के चांसलर फ्रैडरिक मर्ज, अमरीकी बहुराष्ट्रीय निवेश कंपनी, ब्लैकरॉक की जर्मन सब्सीडियरी के सुपरवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। ऐसे हालात में वर्तमान यूरोपीय नेतृत्व से शायद ही इसकी उम्मीद की जा सकती है कि वे अमरीकी हितों के खिलाफ जाकर, ''यूरोपीय हितों'' का झंडा बुलंद करेंगे, जैसा कि पहले के यूरोपीय नेता कर सकते थे, जैसे कि चार्ल्स डि गॉल तथा विली ब्रांट आदि। बहरहाल, यह तथ्य अपने आप में मामूली तो नहीं है कि फिर भी, यूरोप के एक प्रकार आर्थिक आत्महत्या करने का प्रधान कारण मुहैया नहीं कराता है। दरअसल, इसे समझा जा सकता है कि वर्तमान यूरोपीय नेता इसमें विश्वास करते हैं और इसके लिए मंसूबे बना रहे हैं कि अगर यूक्रेन के साथ लड़ाई खिंचती रहती है, तो रूस में निजाम बदल कराया जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो अमरीका के साथ-साथ यूरोप को भी, रूस के विशाल प्राकृतिक संसाधनों तक बेरोक-टोक पहुंच हासिल हो जाएगी। इसके अलावा रूस अब, चीन तथा ईरान समेत, देशों के एक ऐसे गुट का हिस्सा है, जो पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं और इसके वर्चस्व को चुनौती देने की सामर्थ्य रखते हैं। रूस में अगर निजाम बदल करा दिया जाता है, तो इस प्रतिरोध को भी भारी धक्का लगेगा। इतनी ही असाधारण है वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप के जरिए निजाम बदल कराने की अमरीका की डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश। इसके लिए, वहां के वामपंथी राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को, जो ह्यूगो चावेज के उत्तराधिकारी हैं और बोलिवेरियन क्रांति के वारिस हैं, एक ''मादक द्रव्य-आतंकवादी'' और ड्रग कार्टेल के सरगना के तौर पर बदनाम करने के जरिए, जमीन तैयार की जा चुकी है। इस मामले में भी उसकी निगाहें सिर्फ वेनेजुएला के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों पर ही नहीं हैं, जिनमें रेअर अर्थस भी शामिल हैं, उसकी निगाहें इस पर भी हैं कि वेनेजुएला एक साम्राज्यवादविरोधी समूह का भी हिस्सा है, जो साम्राज्यवाद के लिए खतरा बन सकता है। इस तरह, वेनेजुएला में निजाम बदल से साम्राज्यवाद को दोहरा फायदा होगा। बहरहाल, निजाम बदल के डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे, वेनेजुएला से आगे तक जाते लगते हैं। उन्होंने, एक बार फिर स्वीकार साक्ष्य के बिना ही, कोलंबिया के वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को एक ''ड्रग लीडर'' करार दे दिया है, जो ऐसा लगता है कि वहां भी निजाम बदल कराने की भूमिका हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वह इन कोशिशों में कामयाब हो जाते हैं, तो उनके हौसले और बढ़ जाएंगे कि अपना जाल और दूर तक फैलाएं और पूरे लातीनी अमरीका में ही निजाम बदल कराएं, जिसमें क्यूबा भी शामिल हो सकता है।

साम्राज्यवादी देशों का बढ़ता सैन्यीकरण, इन देशों के लिए किसी भी स्रोत से सुरक्षा के लिए किसी बढ़ते खतरे का नतीजा नहीं है। यह नतीजा दुनिया भर में निजाम बदल कराने की उनकी इच्छा का है। ये निजाम बदल उन देशों के खिलाफ कराए जाने हैं, जहां ऐसी सरकारें हैं जो साम्राज्यवाद के वर्चस्व के लिए खतरा पैदा करती हैं। इस खतरे पर अंकुश लगाने के लिए निजाम बदल कराना पिछले कुछ समय में और भी आवश्यक हो गया है क्योंकि साम्राज्यवाद अब ऐसे परिस्थिति संयोग में फंस गया है, जहां अगर तुरंत इससे नहीं निपटा गया तो, यह खतरा बढ़ता ही चला जाएगा। इसकी वजह यह है कि नव-उदारवादी पूंजीवाद अब एक बंद गली में पहुंच गया है, जिसकी अभिव्यक्ति विश्व अर्थव्यवस्था में गतिरोध आने में हो रही है।

सम्पादकीय...

श्रम बाजार

भारत के दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दिशा श्रम बाजार में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी से गहराई से जुड़ी है। जैसे-जैसे नीति-निर्माता और वैश्विक संस्थान महिलाओं की आर्थिक भागीदारी की परिवर्तनकारी क्षमता को उत्तरोत्तर रूप से पहचानने लगे हैं, देश में इस संबंध में उत्साहजनक गति देखने को मिल रही है। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार, 2024 में भारत के महिला श्रम बल की भागीदारी दर (एलएफपीआर) 32.8फीसदी थी-जो वैश्विक दर 48.9फीसदी और पूर्वी एशिया की 59.2फीसदी की तुलना में कम है-फिर भी हाल के वर्षों में महिलाओं के रोजगार में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसकी पहुंच ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों तक है। भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी लंबे समय से विशेषकर घरेलू देखभाल की जिम्मेदारियों जैसी कई सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण प्रभावित रही है। फिर भी, हाल में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से इस दिशा में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज की परिस्थितियां (ओएसएच) संहिता, 2020 समावेशी विकास की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह असुरक्षित कार्यस्थलों और सीमित कानूनी सुरक्षा का सामना करने वाली लाखों महिलाओं के लिए कामकाजी परिस्थितियों को सुरक्षित बनाकर गहन असमानताओं को दूर करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। ओएसएच संहिता स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा के मानकीकृत प्रावधानों को लागू करके, न केवल एक नियामक ढांचे के रूप में कार्य करती है, बल्कि लैंगिक-समानता पर आधारित विकास का उत्प्रेरक भी बनती है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर 41.7 फीसदी हो गई है, जो 2017-18 के 23.3 फीसदी के आंकड़े की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। इस महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद-विशेष रूप से अवैतनिक घरेलू सेवाओं और परिवार के सदस्यों के लिए अवैतनिक देखभाल के कार्यों जैसी चुनौतियां अभी तक बरकरार है। उच्च शिक्षा में बढ़ते महिला नामांकन दर सहित महिलाओं की शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार और घटती साक्षरता खाई के बावजूद यह विरोधाभास कायम है। इस प्रवृत्ति को अक्सर फेमिनाइजेशन यू कर्व कहा जाता है, जो दर्शाती है कि आर्थिक परिवर्तन के दौरान भागीदारी पहले कम होती है और फिर पुनः बढ़ती है। हालांकि, भारत के सामने यह जोखिम है कि वह इस प्रवृत्ति का अपवाद बन सकता है, महिलाओं की लगातार कम भागीदारी न केवल देश के मध्यतम-आय अर्थव्यवस्था में संक्रमण को कमजोर कर सकती है, बल्कि उसके जनसांख्यिकीय लाभांश को भी सीमित कर सकती है। आर्थिक भागीदारी में एक प्रमुख बाधा अवैतनिक देखभाल से संबंधित कार्य का असमान बोझ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के टाइम यूज सर्वे (2024) के अनुसार, भारतीय महिलाएं प्रतिदिन 2 घंटे 17 मिनट अवैतनिक देखभाल से संबंधित सेवाओं में व्यतीत करती है, जबकि पुरुषों का औसत समय 1 घंटे 15 मिनट है। वैश्विक स्तर पर महिलाएं अवैतनिक देखभाल से संबंधित कार्य का लगभग 76फीसदी हिस्सा करती हैं लेकिन भारत में मुख्यतः अपर्याप्त बाल देखभाल ढांचे और सांस्कृतिक अपेक्षाओं के कारण यह बोझ और भी अधिक है- भारत जीडीपीके 15-17फीसदी के बराबर अहमियत रखने वाला यह अवैतनिक श्रम औपचारिक आंकड़ों में आज भी अदृश्य बना हुआ है। यह असमानता कई महिलाओं को नौकरी के अवसर ठुकराने या घर के निकट कम वेतन वाले, अनौपचारिक कार्य स्वीकार करने के लिए बाध्यक करती है। इसके अतिरिक्त, मातृत्व और देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण करियर में आने वाले व्यवधान जीवनभर की आय को कम कर देते हैं जिससे एक स्थायी केयर पेनल्टी उत्पन्न होती है जो दीर्घकालिक आर्थिक सशक्तिकरण को सीमित कर देती है। ओएसएच संहिता, 2020-10 या उससे अधिक श्रमिकों वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा प्रावधानों को मानकीकृत करते हुए 13 श्रम कानूनों को एकीकृत करती है। यह रोजगार और देखभाल से संबंधित कार्य के बीच आने वाली बाधाओं को सीधे तौर पर दूर करती है। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुरूप, यह संहिता मातृत्व अधिकारों पर जोर देती है और कार्यस्थल पर महिलाओं का बने रहना सुविधाजनक बनाने के लिए नर्सिंग ब्रेक सुनिश्चित करती है। महत्वपूर्ण रूप से यह संहिता अनुबंधित और असंगठित श्रमिकों को एक समान सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत ला कर अनौपचारिक क्षेत्र में समानता को बढ़ावा देती है जिससे निर्माण, कृषि और घरेलू कार्य जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को लाभ मिलता है। भर्ती और कार्य की स्थितियों में भेदभाव रहित व्यवस्थाओं को अनिवार्य बनाकर यह कार्यस्थलों को अधिक सुरक्षित और लैंगिक-चुनौतियों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाती है, जिनके कारण ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को कार्यबल से बाहर रखा जाता रहा। अन्य क्षेत्रों के अनुभव इस बात की पुष्टि करते हैं कि लैंगिक-संवेदनशील ओएसएच ढांचे बदलाव का एक शक्तिशाली साधन है। स्वीडन और आइसलैंड में, कार्यस्थल सुरक्षा, सब्सिडी वाली बाल देखभाल और माता-पिता की छुट्टियों को एकीकृत करने वाले सामाजिक सुरक्षा ढांचों के माध्यम से श्रम बल में महिलाओं की 70फीसदी से अधिक भागीदारी दर हासिल की गई है। जापान और दक्षिण कोरिया में, कार्यस्थल सुरक्षा और क्रेच सुविधाओं का विस्तार करके महिलाओं की एलएफपीआर धीरे-धीरे सुधारी जा रही है। उप-सहारा अफ्रीका में कृषि क्षेत्र में कानूनी सुरक्षा ने महिलाओं की भागीदारी को 70फीसदी तक बढ़ाने में मदद की है। लैटिन अमेरिकी उदाहरण, जैसे कि चिली और उरुग्वे, दर्शाते हैं कि सरकार द्वारा वित्तपोषित बाल देखभाल महिलाओं के रोजगार को बढ़ाती है, जबकि बच्चों के विकास पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता। भारत के लिए, ये उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि ओएसएच सुरक्षा उपायों को देखभाल संबंधी अवसंरचना में निवेश के साथ जोड़ना परिवर्तनकारी परिणाम सामने लाएगा। ओएसएच संहिता, 2020 दीर्घकालिक और लैंगिक-संवेदनशील विकास के लिए एक रणनीतिक साधन है। इसकी पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए इसे एक ऐसे इकोसिस्टम में काम करना होगा जो कार्यस्थल की परिस्थितियों और देखभाल से संबंधित कार्य के बोझ दोनों पर गौर करता हो।

डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट गम्भीर

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में साइबर अपराध एक गंभीर चुनौती बन गया है। इसमें हैकिंग, डेटा चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, साइबरबुलिंग और मैलवेयर फैलाने जैसे अवैध कार्य शामिल हैं। ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से लेकर दैनिक कार्यों के लिए कंप्यूटर पर निर्भर व्यवसायों तक, कई लोग साइबर अपराधों का अनुभव करते हैं। उदाहरणों में फ़िशिंग ईमेल के माध्यम से पहचान की चोरी, फ़ाइलों को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाले ऑनलाइन घोटाले शामिल हैं। इन अपराधों के परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान, भावनात्मक संकट और प्रतिष्ठा को नुकसान होता है। दुनियाभर की सरकारें सख्त कानून बना रही है और साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है लेकिन व्यक्ति भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपकरणों को अपडेट करना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना और संवेदनशील जानकारी को ऑनलाइन साझा करने से बचना साइबर अपराध को रोकने में मदद कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों और वित्तीय संस्थानों और ईडी जैसी जांच एजेंसियों द्वारा बार-बार लोगों को आगाह किए जाने के बावजूद डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट से ठगी का शिकार होने वाले शिक्षित वर्ग, पूर्व पुलिस अधिकारी, सेवानिवृत्त और मौजूदा नौकरशाह, युवा और वृद्ध महिलाएं भी हो रही हैं। डिजिटल अरेस्ट की पूरी प्रक्रिया लगभग तय है। आपको एक कानून प्रवर्तन अधिकारी का फोन आता है जो आपको एक गम्भीर अपराध में फंसा हुआ बताता है। फिर फोन करने वाला आपको वीडियो काल के जरिए दूसरे आला अफसरों से मिलाने की पेशकश करता है। बदले में वह कानूनी लड़ने में आरोपों की व्याख्या करता है और आपके दावों को न्याय व्यवस्था से पुष्ट करता है। जांच के दौरान आप को घर या यहां तक कि किस कमरे में आप हैं वहां से बाहर न निकलने और किसी और से बात न करने के लिए कहा जाता है। आपको कड़े निर्देश दिए जाते हैं कि आपको अपना लेपटॉप कैमरा या फोन बंद नहीं करना है। आपकी रोजमर्रा गतिविधियों पर कभी-कभी तो कई दिनों तक सवालों की झड़ी लगाकर नजर रखी जाती है। इसके बाद आती है गिरफ्तारी या आगे की कानूनी लड़ाई के बदले में एक बड़ी रकम। तब तक आप डरे, सहमे थक चुके होते है और बचने के लिए आप पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। फोन अचानक खामोश हो जाता है। पूछताछ करने वाले चले जाते है और आपकी जिन्दगी भर की कमाई का पैसा बिना कोई निशान छोड़ गायब हो जाता है। एक सरकारी अनुमान के अनुसार पिछले वर्ष भारतीयों को लगभग 1 लाख 20 हजार से ज्यादा ऐसे घोटालों में 19 अरब रुपए का नुकसान हुआ। चिंताजनक बात यह है कि 2022 और 2024 के बच डिजिटल गिरफ्तारी, धोखाधड़ी के दर्ज मामलों की संख्या लगभग तीन गुणा हो गई है। साइबर अपराधी सीमाहीन व्यापार के समान अवसर प्रदान करने वाले अपराधी हैं। उनका दायरा बहुत बड़ा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 में वैश्विक साइबर अपराध की आर्थिक लागत 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होगी। डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी भारतीयों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती नजर आ रही है। पीड़ितों में शिक्षाविद, बैंकर, व्यवसायी और डॉक्टर भी शामिल हैं। साइबर अपराध के आघात से उभरने में असमर्थ कुछ लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं। यद्यपि साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारत में कानून कड़े किए गए है। इसके बावजूद लोग स्कैम का शिकार हो रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते डिजिटल अरेस्ट घोटाले का संज्ञान लेते हुए सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के सभी मामलों की जांच का निर्देश दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि साइबर अपराधियों के संगठित गिरोह काम कर रहे है और उनके तार संभव है कि बैंकिंग क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। शीर्ष अदालत ने सीबीआई जांच को मजबूत करने के लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं। सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बैंकरों की भूमिका की जांच करने की पूरी छूट होगी, जहां डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले के उद्देश्य से बैंक खाते खोले गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से इस न्यायालय की सहायता करने के लिए कहा गया है कि क्या ऐसे संदिग्ध खातों की पहचान करने और अपराध की ऐसी आय को रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मशीन लर्निंग को लागू किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ नियम 2021 के तहत अधिकारियों को जांच के दौरान आवश्यकतानुसार सीबीआई के साथ सहयोग करने का आदेश दिया गया है। जिन राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में जांच के लिए सीबीआई को सहमति नहीं दी है। उन्हें जांच के लिए सहमति देने का निर्देश दिया गया है। ताकि सीबीआई अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक कार्रवाई कर सके। ऐसे अपराधों की गंभीरता और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये अपराध भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर भी हो सकते हैं। सीबीआई को आवश्यकता पड़ने पर इंटरपोल प्राधिकारियों से सहायता के लिए अनुरोध करना चाहिए। दूर संचार सेवा प्रदाता एक ही नाम से कई सिमकार्ड जारी कर लापरवाह रवैया अपना रहे हैं। कोर्ट ने सिमकार्ड का दुरुपयोग रोकने के लिए भी निर्देश दिए है। धोखाधड़ी के लिए साइबर अपराधी अलग-अलग शब्द गढ़ते रहते हैं। जैसे पार्ट टाइम नौकरियों के घोटाले में प्रलोभन देकर अभ्यर्थियों से रकम वसूली जाती है। लोग भी कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका के साथ उलझने के डर से अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। साइबर अपराधी बड़े-बड़े जजों के नाम का इस्तेमाल भी करने से नहीं चूक रहे। भारतीयों के लिए किसी अंजान नम्बर से आया एक फोन काल ही उनकी जिन्दगी में उथल-पुथल मचाने के लिए काफी है। बेहतर यही होगा कि लोग जागरूक बनें और ऐसे फोन कॉल आने पर हड़बड़ाहट में कोई कदम न उठाएं तभी इससे बचा जा सकता है।

पुतिन के भारत दौरे से पहले फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के राजदूतों ने तोड़ी कूटनीतिक मर्यादा

हम आपको बता दें कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के राजदूतों– थियेरी मथू, फिलिप अकरमैन और लिन्डी कैमरन ने सोमवार को एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र में संयुक्त लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन पर यूक्रेन में शांति प्रयासों को बाधित करने का आरोप लगाया। लेख में लिखा था कि दुनिया चाहती है कि युद्ध समाप्त हो, लेकिन रूस गंभीर नहीं दिखता। तीनों राजदूतों ने लेख में भारत की स्थिति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के कथन– समाधान युद्धभूमि पर नहीं मिल सकता, को भी उद्धृत किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस लेख को अनुचित बताया और कहा कि किसी तीसरे देश के नेता की भारत यात्रा से ठीक पहले इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी कूटनीतिक संवेदनशीलता के विरुद्ध है। अधिकारियों के अनुसार, भारत ने इस असामान्य कदम को नोट किया है। देखा जाये तो फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के राजदूतों द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित लेख केवल असामान्य ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की स्थापित मर्यादाओं के संदर्भ में एक गंभीर कूटनीतिक अशिष्टता माना जा रहा है। कूटनीति का मूल सिद्धांत यह है कि किसी मेजबान देश में पदस्थ राजनयिक किसी तृतीय देश के शीर्ष नेतृत्व की यात्रा के समय ऐसी सार्वजनिक टिप्पणियों से परहेज करें, जो उस यात्रा के उद्देश्य या वातावरण को प्रभावित कर सकती हों। राजनयिक आचार संहिता–विशेषकर वियना राजनयिक संबंध संधि (1961) की भावना स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा रखती है कि राजदूत मेजबान देश की घरेलू या संवेदनशील द्विपक्षीय प्रक्रियाओं में न तो हस्तक्षेप करें और न ही सार्वजनिक रूप से ऐसा आभास होने दें। इस लिहाज से, तीनों यूरोपीय दूतों द्वारा प्रकाशित लेख न केवल भारत-रूस वार्ता के पूर्व निर्धारित कूटनीतिक संतुलन में अनावश्यक व्यवधान डालता है, बल्कि यह एक प्रकार की ऐसी पब्लिक डिप्लोमेसी का प्रयोग बन जाता है, जो किसी निष्पक्ष मध्यस्थ वातावरण को बाधित कर सकता है। कूटनीति का सार यही है कि संवाद बंद न हो और संवाद तभी निष्पक्ष माना जाएगा जब राजदूतों का सार्वजनिक आचरण समय, भाषा और उद्देश्य, तीनों में संयमित और संतुलित रहे। तीनों राजदूतों के संयुक्त आलेख से एक सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत–रूस निकटता से असहज है यूरोपीय देश? देखा जाये तो इस संयुक्त लेख के समय और स्वर से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोपीय देशों में भारत–रूस रणनीतिक निकटता को लेकर एक प्रकार की अंतर्निहित असहजता साफ दिखाई दे रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने का प्रयास किया था तब भारत ने अपने दीर्घकालिक सामरिक हितों और ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर रूस के साथ संवाद और व्यापार को जारी रखा। इससे यूरोपीय राजधानियों में यह भावना बनी रही कि भारत, उनके व्यापक भू-राजनीतिक आकलन से अलग प्राथमिकताएं रखता है। ऐसे में पुतिन की दिल्ली यात्रा से ठीक पहले तीन यूरोपीय राजदूतों का एकसाथ सार्वजनिक लेख लिखना एक संदेश-प्रधान कूटनीतिक कदम भी माना जा सकता है। तीनों राजदूतों के संयुक्त आलेख से एक सवाल यह भी उठता है कि यूरोपीय राजदूतों ने ऐसा लेख किसी और देश में क्यों नहीं लिखा? देखा जाये तो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन कई देशों की यात्राएं कर चुके है।

जागरूक मतदाता-लोकतंत्र की वैश्विक जिम्मेदारी और 100 प्रतिशत सहभागिता की आधुनिक अनिवार्यता

वैश्विक स्तरपर लोकतंत्र किसी भी राष्ट्र का केवल राजनीतिक ढांचा नहीं बल्कि सामाजिक चेतना, नागरिक अधिकारों और जनभागीदारी की संयुक्त अभिव्यक्ति है। विश्व के हर बड़े लोकतंत्र भारत, अमेरिका फ्रांस,जापान,जर्मनी,ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका ने यह स्पष्ट रूप से सीखा है कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतांत्रिक संस्थाएं मात्र औपचारिक ढांचे में बदलकर रह जाती हैं।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि ऐसे समय में मतदाताओं का मतदान के प्रति उत्साह किसी भी राष्ट्र के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य का सबसे विश्वसनीय सूचक माना जाता है। जब नागरिक स्वयं यह मान लें कि लोकतंत्र केवल सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा एक सामाजिक अनुशासन है, तब मतदान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।इसी व्यापक दृष्टि के साथ आज मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 को गोंदिया नगर परिषद के नगर अध्यक्ष और दो पार्षदों के लिए मतदान केवल एक स्थानीय नागरिक दायित्व नहीं,बल्कि वैश्विक लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। किसी छोटे नगर में होने वाला एक वोट भी विश्व लोकतंत्र के उस विशाल कैनवास पर प्रभाव छोड़ता है, जहां नागरिक भागीदारी, राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक उत्तरदायित्व आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। मतदान का हर कदम इस तथ्य को मजबूत करता है कि लोकतंत्र तभी सुरक्षित है जब उसका हर नागरिक खुद को इस व्यवस्था का सक्रिय रक्षक समझता है।गोंदिया जैसे नगर में यदि मतदान का प्रतिशत अधिक होता है, तो यह सिर्फ एक स्थानीय उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को वैश्विक स्तर पर यह संदेश देगा कि यहां के नागरिक हर परिस्थिति में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सर्वोच्च महत्व देते हैं। आज विश्व में कई लोकतंत्र मतदाता उदासीनता,गलत सूचना और जन विश्वास संकट से गुजर रहे हैं। उनके मुकाबले यदि किसी भारतीय नगर में 100 प्रतिशत मतदान के लक्ष्य की आवाज उठती है, तो यह केवल भारत ही नहीं,बल्कि पूरे विश्व लोकतांत्रिक समुदाय के लिए प्रेरणा का विषय बन सकता है। साथियों बात अगर हम मतदाताओं का उत्साह-लोकतंत्र को मजबूत बनाने की सार्वभौमिक शक्ति है इसको समझने की करें तो, विश्व इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहाँ कम मतदान या मतदाता उदासीनता ने लोकतंत्र को कमजोर किया और राजनीतिक ढांचों को अस्थिरता की ओर धकेल दिया।राजनीतिक अस्थिरता,जन असंतोष,भ्रष्टाचार और प्रशासनिक असमताएं अक्सर वहीं अधिक पनपती है जहाँ नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग कम करते हैं। इसके विपरीत, जहाँ मतदाता जागरूक होते है और 70-80 प्रतिशत या उससे भी अधिक मतदान दर दर्ज की जाती है, वहाँ की राजनीतिक प्रणाली अधिक पारदर्शी,जवाबदेह और सहभागी बनती है।मतदाताओं का उत्साह केवल वोट देने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहता बल्कि राजनीति में जनता की भूमिका को उच्च स्तर पर ले जाता है। यह उत्साह राजनीतिक दलों को भी संदेश देता है कि जनता अब निष्क्रिय नहीं है,वह शासन, निर्णय और नीतियों पर नजर रखती है। इस जागरूकता से शासन तंत्र में सुधार, अधिक पारदर्शिता, कुशल सेवा वितरण और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप नीतियों का निर्माण सहज और सटीक रूप से आगे बढ़ता है। साथियों बात अगर हम जागरूक मतदाता बनने की वैश्विक जिम्मेदारी लोकतंत्र को 100 प्रतिशत भागीदारी तक ले जाने का संकल्प करने की करें तो, 21वीं सदी की राजनीति में वैश्विक लोकतंत्र अनेक दबावों से गुजर रहा है डिजिटल गलत सूचना,सोशल मीडिया पर पूर्वाग्रह निर्माण,चुनावों में धन बल का प्रभाव,राजनीतिक ध्रुवीकरण,और नॉन डेमोक्रेटिक विचारधाराओं का उभार।

ऐसे समय में जागरूक मतदाता होने का अर्थ केवल मतदान करना नहीं, बल्कि सूचित मतदान, विवेकपूर्ण निर्णय औरसामाजिक जिम्मेदारी निभाना भी है जागरूक मतदाता तीन प्रमुख भूमिकाएँ निभाता है (1)तथ्यों पर आधारित निर्णय लेने वाला नागरिक,(2) लोकतंत्र को दिशा देने वाला सक्रिय सहभागी,(3) वैश्विक लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षक और संवाहकइस संदर्भ में 100 प्रतिशत भागीदारी केवल एक सांख्यिकीय लक्ष्य नहीं,बल्कि लोकतांत्रिक आदर्शवाद का आधुनिक रूप है। दुनिया के लोकतांत्रिक विशेषज्ञ आज यह तर्क देते है कि जितनी अधिक भागीदारी, उतना अधिक मजबूत लोकतंत्र।100 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य एक नगर या शहर की सीमाओं से बहुत आगे जाकर राष्ट्र और विश्व को यह संदेश देता है कि नागरिक लोकतंत्र के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

गोंदिया नगर अगर 100 प्रतिशत मतदान की दिशा में कदम बढ़ाता है, तो यह केवल स्थानीय स्तर पर स्वर्णिम क्षण नहीं होगा, बल्कि यह विश्व लोकतंत्र के लिए एक नया अध्याय होगा जो यह बताएगा कि विकसित होते समाज में नागरिकों की सक्रियता किस तरह लोकतांत्रिक ढांचे को नई ऊर्जा से भर देती है।आज, जब कई देशों में मतदान प्रतिशत गिर रहा है, भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के छोटे नगर यदि 100 प्रतिशत मतदान की मिसाल रखते है, तो यह लोकतंत्र के भविष्य को लेकर एक सकारात्मक वैश्विक संदेश है कि राजनीतिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी अभी भी सबसे शक्तिशाली परिवर्तनकारी शक्ति है। साथियों बात अगर हम आज 2 दिसंबर 2025 को गोंदिया में मतदान-स्थानीय कर्तव्य से वैश्विक प्रतिबद्धता तक की यात्रा इसको समझने की करें तो,आज 2 दिसंबर 2025 को गोंदिया नगर परिषद चुनाव में मतदान करना केवल एक व्यक्तिगत दायित्व नहीं बल्कि वह वैश्विक विमर्श भी है जो लोकतंत्र की रक्षा और सुदृढ़ीकरण के लिए विश्व स्तर पर चल रहा है। जब एक नागरिक सुबह उठकर मतदान केंद्र तक जाता है,अपनी पहचान दर्ज कराता है, और ईवीएम मशीन के सामने खड़े होकर एक बटन दबाता है तो यह एक साधारण घटना लग सकती है। लेकिन वास्तव में यह वैश्विक लोकतंत्र की बुनियाद में जुड़ने वाली एक महत्वपूर्ण अमूल्य ईंट होती है। साथियों बात कर हम विश्वभर में कई सामाजिक वैज्ञानिक के विचारों को समझने की करें तो वे यह मानते है कि लोकतंत्र और नागरिक भागीदारी के बीच जितना गहरा संबंध भारत जैसे देशों में देखने को मिलता है, उतना कम ही अन्य स्थानों पर दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि यहाँ लोकतंत्र जन आंदोलनों संघर्षों और सामाजिक जागृति की लंबी यात्रा से विकसित हुआ है। इसलिए भारत का हर नागरिक अपने वोट के महत्व को भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक सभी आधारों पर गंभीरता से समझ सकता है। गोंदिया के चुनावों में मतदान करने के बाद महसूस होने वाला गर्व केवल इसलिए नहीं है कि हमने अपना दायित्व निभाया, बल्कि इसलिए भी कि आपने विश्व लोकतंत्र के स्वास्थ्य में अपना योगदान दिया। आपका वह वोट वैश्विक समुदाय को यह बताता है कि नागरिक चाहे किसी भी स्तर के चुनाव में हो नगर जिला, राज्य या केंद्र उनकी चेतना राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा के लिए पूरी तरह जागृत है। साथियों बात अगर हम मतदान- राजनीतिक संस्कृति का सशक्त स्तंभ इसको समझने की करें तो, राजनीतिक संस्कृति केवल सरकार, संविधान या राजनीतिक दलों से नहीं बनती,वह बनती है नागरिक चेतना से। मतदान इस संस्कृति का सबसे सशक्त स्तंभ है। यह नागरिकों को यह अहसास दिलाता है कि वे केवल शासन के विषय नहीं बल्कि व्यवस्था के निर्माता हैंमतदान यह सुनिश्चित करता है कि (1) सत्ता जवाबदेह बनी रहे,(2) नीतियाँ जनता-केंद्रित रहें,(3) नेताओं का चुनाव मेरिट, नीतियों और जनहित के आधार पर हो,(4) समाज में समानता, न्याय और पारदर्शिता की भावना बने।जब नागरिक मतदान से दूर रहते है, तो वे अनजाने में अपने भविष्य के निर्णयों का अधिकार दूसरों को सौंप देते है। लेकिन जब वे सक्रिय होकर आगे आते है, तो लोकतंत्र अधिक स्थिर, मजबूत और जनउत्तरदायी बनता है। साथियों बात अगर हम गलत सूचना, ध्रुवीकरण और वैश्विक चुनौतियों के युग में मतदान के महत्व को समझने की करें तो, आज दुनिया का हर बड़ा लोकतंत्र गलत सूचना, गहरे राजनीतिक ध्रुवीकरण, और डिजिटल प्रोपेगेंडा जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल इकोसिस्टम ने सूचनाओं को तेज बनाया है, परंतु उनकी विश्वसनीयता को कमजोर भी किया है।

ऐसे माहौल में नागरिकों के लिए सूचित निर्णय लेना आसान नहीं रहा।इसलिए, जागरूक मतदाता का महत्व और बढ़ जाता है। वह (1) तथ्य और अफवाह के बीच अंतर करता है, (2) प्रचार और वास्तविकता को अलग पहचानता है, (3) मताधिकार को भावनाओं नहीं, विवेक से जोड़ता है, (4) और राजनीतिक भाषा के बजाय नागरिक हितों को प्राथमिकता देता है। गोंदिया में मतदान कर लौटना इस जागरूकता का प्रमाण है कि नागरिक तथ्य आधारित निर्णय लेते है और लोकतंत्र को गलत सूचना तथा भ्रामक प्रचार के हमलों से बचाने के लिए तैयार है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/38862)

कड़ी सुरक्षा में हुआ सैनिक का अंतिम संस्कार, दिया गॉर्ड ऑफ हॉनर, पिता ने दी मुखाग्नि

प्रयागराज ,यमुनानगर

(करछना)। थाना क्षेत्र में सैनिक विवेक सिंह की मौत के बाद जब शव करछना पहुंचा, तो परिवार में कोहराम मच गया।

विवेक का शव देखकर परिवार के लोग बिलख पड़ेापत्नी भी बेसुध हो गई। सुबह में कड़ी सुरक्षा के बीच करछना स्थित मनैया घाट पर जवान का अंतिम संस्कार किया गया। पिता उमाकांत सिंह ने नम आंखों से मुखाग्नि दी।अंतिम संस्कार से पहले सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ आनर दिया गया।बीते 29 नवंबर को स्कॉर्पियो को ओवरटेक करने को लेकर सेना के हवलदार, एक दरोगा, व तीन अन्य साथियों ने लोहे की राड से मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में करछना पुलिस ने पांचो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धरवारा गांव निवासी विवेक सिंह28 पुत्र उमाकांत सेना के इंटेलिजेंस विभाग में दिल्ली में तैनात थे।पिता उमाकांत सिंह सेवा में सूबेदार पद से रिटायर हुए हैं।विवेक सिंह दो भाइयों में छोटे थे,और 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी।विवेक की पत्नी प्रतिभा व 2 वर्षीय पुत्र वेदांत है। वह अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी पर घर आए थे।शनिवार देर रात वह अपनी कार से कोहड़ार से लौटते समय धरवारा मोड़ के पास पीछे से आ रही स्कार्पियो सवार कुछ लोगों से ओवरटेक करने को लेकर उनका विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर स्कार्पियो सवार लोगों ने विवेक सिंह के सर पर लोहे की राड से हमला कर दिया,और उन्हें बुरी तरह पीट कर अधमरा कर दिया। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। घर वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जवान को लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां बीती रात उनकी मौत हो गई। हमलावर चक, नैनी के रहने वाले हैं। पुलिस ने सेना के हवलदार राजीव कुमार ,राजकमल पांडे, दरोगा दिनेश कुमार यादव,राजीव अग्रहरि,भाईलाल यादव निवासी चक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

टीएमयू में नर्सिंग के स्पोर्ट्स इवेंट ब्रह्मोत्सव का शंखनाद

मुरादाबाद।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के वीसी प्रो. वीके जैन ने कहा, स्पोर्टस स्टुडेंट्स के जीवन का अभिन्न अंग है। विशेषकर नर्सिंग स्टुडेंट्स खेलों को आत्मसात करें। उन्होंने छात्र-छात्राओं की हौसलाफजाई करते हुए कहा, स्टुडेंट्स के शरीरिक और मानसिक ग्रोथ के लिए ब्रह्मोत्सव इवेंट में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। वीसी प्रो. जैन कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट- ब्रह्मोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इससे पूर्व मुख्य अतिथि प्रो. वीके जैन ने शांति के प्रतीक कबूतर और गुब्बारे उड़ाकर चार दिनी ब्रह्मोत्सव का शंखनाद किया। इस मौके पर डायेक्टर गवर्नेंस नीलिमा जैन, फैकल्टी आफ इजीनियरिंग के डीन प्रो. आरके द्विवेदी, आईक्यूएसी के डायरेक्टर प्रो. निशीथ मिश्रा, नर्सिंग कॉलेज की डीन प्रो. एसपी सुभाषिनी, नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. जेसलीन एम., पार्श्वनाथ नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. श्योली सेन, 'वाइंट रजिस्ट्रार डॉ. वैभव रस्तोगी आदि की उल्लेखनीय मौजूदगी रही। इस मौके पर छात्र-छात्राओं ने कल्चरल प्रोग्राम्स की प्रस्तुति भी दी। रंगारंग परिधानों में नर्सिंग छात्रों के चार ग्रुपों- वायु, नीर, आकाश और अग्नि ने मार्च पास्ट में प्रतिभाग किया। मार्च पास्ट की भव्यता और अनुशासन देखते ही बनता था। इन चार ग्रुपों में मार्च पास्ट का प्रथम पुरस्कार टीम अग्नि की झोली में गया। द्वितीय पुरस्कार टीम नीर और तृतीय पुरस्कार पर टीम वायु का कब्जा रहा। ओपनिंग सेरेमनी के बाद खेल प्रतियोगिताओं में तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और तीर्थंकर पार्श्वनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र-छात्राओं ने खूब पसीना बहाया । ब्रह्मोत्सव के तहत टग ऑफ वार और कबड्डी की प्रतियोगिताएं हुईं। टग ऑफ वार की प्रतियोगिता के ब्वायज ग्रुप में वायु टीम और गर्ल्स ग्रुप में नीर टीम 2-1 से विजेता रहीं। इस मौके पर प्रो. विजी मोल, डॉ. सपना सिंह, प्रो. जितेन्द्र सिंह, प्रो. अनुषी सिंह, डॉ. सुमन वशिष्ठ, डॉ. रामकुमार गर्ग के संग-संग स्पोर्टस कोर्डिनेटर्स- पूजा झा, सतीश प्रजापति, रितिक कुमार, विनय लाल आदि की उल्लेखनीय मौजूदगी रही। चंद्रशेखर टग ऑफ वार के निर्णायक रहे।

पात्र गृहस्थी राशन कार्डो का विधायक ने किया वितरण

मुरादाबाद।

कुंदरकी विधानसभा के ग्रामों से प्राप्त राशन कार्ड आवेदनों को पूर्ति विभाग द्वारा सत्यापित करने के पश्चात आज ब्लॉक सभागार कुंदरकी में 421 एवं ब्लॉक सभागार मूंढापांडे में 467 लाभार्थियों को पात्र गृहस्थी राशन कार्ड कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने वितरित किए। इस अवसर पर कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने बताया कि अगले माह तक कुंदरकी विधानसभा में कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड ये वंचित नहीं रहेगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव गांव जाकर पात्र परिवारों से आवेदन कराए है। जिस राशन कार्ड को बनवाने के लिए पहले लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, आज लाभार्थी के घर आवेदन फॉर्म पहुंच रहा है। ये आपके वोट की ताकत जो आपने मुझे एक साल पहले दी, उसकी बदौलत में ये कर पा रहा हूँ। मेरा ये प्रण है मेरी विधानसभा में कोई भी व्यक्ति केंद्र और रा'य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। तमाम योजनाएं जो पहले धरातल तक नहीं पहुंचती थी आज हमारे कार्यकर्ता उन योजनाओं की जानकारी आपके घर-घर तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना की बदौलत आज कोई गरीब व्यक्ति भूख नहीं सोता है। आज पूरा राशन मिल रहा है और समय पर मिल रहा है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष संजय कश्यप, बबलू सैनी, नीरज चंद्रा, महेंद्र सैनी, ब्लॉक प्रमुख कुंदरकी प्रतिनिधि गुलाम जिलानी, ब्लॉक प्रमुख मुंडापांडे डॉ नवदीप यादव, नूरी मौलाना, रोहित सिंह, सोनू रस्तौगी, रामकिशोर लोधी सहित पूर्ति विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

अभियान चलाकर चिन्हित किये गये बाल श्रमिक

मुरादाबाद।

उप श्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट के निर्देशन में श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम द्वारा मुरादाबाद के बंगला गांव एवं जिगर विहार कालोनी में बाल एवं किशोर श्रमिक चिन्हांकन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 04 प्रतिष्ठानो से 05 बाल श्रमिको का चिन्हांकन किया गया तथा 02 प्रतिष्ठान से 03 किशोर श्रमिक को चिन्हित किया गया। चिन्हित समस्त 05 बाल श्रमिकों को उनके आयु परीक्षण हेतु सम्बन्धित श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके पश्चात् उनकी सुपुर्दगी हेतु बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की गयी। इन प्रतिष्ठान के नियोजको द्वारा बाल एवं किशोर श्रम(प्रतिशोध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 के अधिनियम का उल्लंघन किये जाने के कारण सम्बन्धित नियोजको के विरूद्ध अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण टिप्पणी निर्गत कर मौके पर ही हस्तगत करा दी गयी है तथा प्रकरण में निरीक्षणोपरान्त अग्रिम कार्यवाही अपनायी जा रही है। उप श्रमायुक्त द्वारा नियोजको को भविष्य मे बाल एवं किशोर श्रमिकों से कार्य न लिये जाने हेतु सचेत किया गया।

घर पहुंचकर बढ़ाया दिव्यांग छात्र का हौंसला

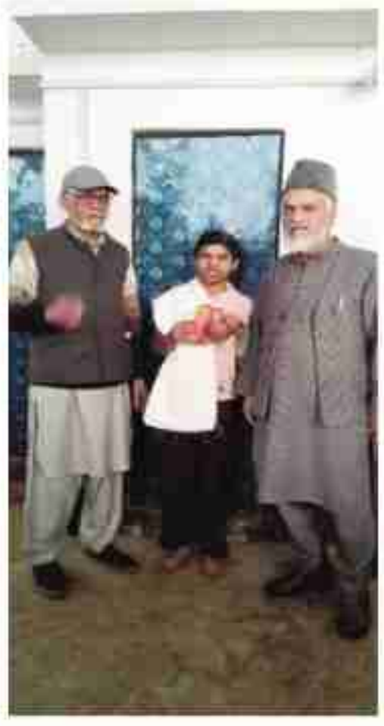

मुरादाबाद।

नेशनल सोशल ऑर्गनाइजेशन (एनएसओ) ने आज विश्व दिव्यांग दिवस पर एक कक्षा पाँच के दिव्यांग विद्यार्थी मौ. अरकान पुत्र दिलदार हसन जो घोसी बिरादरी से है तथा जिसका हाथ चरी काटने वाली मशीन में आकर कट गया था। इस बच्चे को उसके घर स्थित मौहल्ला नवाबपुरा जाकर संगठन के अध्यक्ष मिर्जा अरशद बेग व उपाध्यक्ष शफ़ात अहमद खाँ ने शॉल उढ़ाकर तथा उपहार भेंट करके उसकी हिम्मत को पदाधिकारियों नसराहा कि वह शिक्षा प्राप्त करके किसी काबिल बनना चाहता है।

इस अवसर पर संगठन के उक्त पद दिव्यांगों के साथ हमदर्दी व उनकी हर सम्भव सहायता को धर्मिक व व्यवहारिक कर्तव्य बताया तथा दिव्यांगों से भी अपील की है कि वह अपने प्रयासों से आगे बढ़कर यह साबित करदें कि इरादों व हौसलों से हर मुशकिल आसान हो जाता है।

फिलिपींस की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसः पैरामेडिकल की टीएमयू की तीन सीनियर्स फैकल्टी ने दिया व्याख्यान

मुरादाबाद।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद की तीन सीनियर फैकल्टीज़ ने यूनिवर्सिटी ऑफ फिलिपींस की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म साझा किया। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थीम- फॉरेंसिक्स ऑफ द फॉरगॉटनः अनकवरिंग मेमोरी, कल्चर एंड आइडेंटिटी इन द ग्लोबल साउथ रही। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में टीएमयू के कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज़ की मेडिकल लैब टेक्निक्स की एचओडी प्रो. रूचि कांत, फॉरेंसिक के एचओडी श्री रवि कुमार और सीनियर फैकल्टी श्री योगेश कुमार ने अपने-अपने टॉपिक्स पर व्याख्यान दिए। ऑनलाइन आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में प्रो. रूचि कांत ने बायोकेमिकल पाथवेज़ ऑफ़ रेज़िलिएंसः अंडरस्टैंडिंग हेल्थ, जेंडर, एंड एजिंग इन पोस्ट-क्राइसिस

कॉनटेक्स्ट्स, रवि कुमार ने एमर्जिंग फ्रंटियर्स इन फ़ॉरेंसिक साइंस एजुकेशन एंड इनोवेशनः बिल्डिंग कैपेसिटीज़ फ़ॉर द ग्लोबल साउथ और योगेश कुमार ने टैफ़ोनॉमी एंड फ़ॉरेंसिक एंटोमोलॉजीः रिकन्स्ट्रक्टिंग डेथ एंड मेमोरी इन ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स पर अपने-अपने विचार साझा किए। प्रो. रूचि कांत ने कहा, लचीलापन (रेजिलिएंस) समन्वित न्यूरोएंडोक्राइन, इम्यून और मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। संकट के बाद का तनाव कोर्टिसोल नियमन, सूजन, न्यूरोप्लास्टिसिटी और आंत-मस्तिष्क सिग्नलिंग को बदल देता है। लिंग और उम्र इन मार्गों को हार्मोनल बदलावों जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, मेनोपॉज और एंड्रोपॉज के माध्यम से प्रभावित करते हैं। जैविक, सामाजिक और लिंग-विशिष्ट तंत्रों को मजबूत करने से रिकवरी तेज होती है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। श्री रवि कुमार ने बताया, फॉरेंसिक में क्या-क्या गैप्स हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों जरूरी है। उन्होंने एआई, नैनोटेक्नोलॉजी, वर्चुअल अटोप्सी, थ्रीडी इमेजिंग, इथिक्स एंड पॉलिसी चैलेंजेज़, रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंटरनेशनल कोलाबोरेशन, करिकुलम मॉर्डनाइजेशन एंड रिकमांडेशन की फॉरेंसिक साइंस में भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। योगेश कुमार ने फोरेंसिक टैफोनोमी पर प्रकाश डालते हुए बताया,मृत्यु के बाद मानव शरीर के साथ क्या होता है। बाहरी वातावरण में शरीर के साथ जो कुछ भी होता है, वह पौधों, जानवरों, मिट्टी, पर्यावरण कई अन्य प्राकृतिक कारकों से हुए परिवर्तन का परिणाम होता है। शव पर पाए जाने वाले कीड़ों, जैसे ब्लो फ्लाई के लार्वा के जीवन चक्र का विश्लेषण करके, फोरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट यह अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु कब हुई।

दिल्ली के राज निवास का नाम बदला, एलजी ने लिया फैसला, आदेश लागू

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का राज निवास अब लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने बड़ा फैसला लेते हुए राज निवास का नाम बदलकर अब लोक निवास कर दिया है। गृह मंत्रालय के 25 नवंबर 2025 के आदेश के बाद यह बदलाव बुधवार (03 दिसंबर) से लागू हो गया है। गृह मंत्रालय का आदेश लागू होने के बाद अब दिल्ली का राज निवास आधिकारिक तौर पर लोक निवास कहलाएगा। इस बदलाव की जानकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, सभी राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्री कार्यालयों सहित अन्य बड़े विभागों को भेज दी गई है। देशभर के राजभवनों का नाम 'लोक भवन' करने संबंधी गृह मंत्रालय के 25 नवम्बर के निर्देश का मुद्दा राज्यसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सदस्य डोला सेन द्वारा उठाए जाने के बाद सदन में तीखी नोकझोंक हुई। शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए जब डोला सेन ने कहा, ''सबसे पहले हम यह कहना चाहते हैं कि न तो संसद, विधानसभा और न ही मंत्रिमंडल को इसकी जानकारी है और तो और मंत्रीगण, वे आपस में भी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।'' अपनी बात रखने के दौरान डोला सेन ने मनरेगा सहित अन्य मुद्दों का भी जिक्र किया, तब सभापति ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदस्य अपने मूल विषय पर ही बोलें और विषय से अलग बातें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगी। सदन के नेता जे पी नड्डा ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, ''आपने उन्हें शून्यकाल में राजभवन का नाम लोक भवन करने के मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी थी। लेकिन उन्होंने मनरेगा और अन्य मुद्दों का जिक्र किया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि चूंकि यह विषय से संबंधित नहीं है, इसलिए इसे कार्यवाही से हटा दिया जाए और केवल लोक भवन से जुड़ी बातें ही रिकॉर्ड में ली जाएं।'' सभापति सी पी राधाकृष्णन ने नड्डा से सहमति जताते हुए दोहराया कि ''विषय से हटकर कहा गया कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।'' विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने डोला सेन के समर्थन में कहा, ''उन्होंने कोई भी अपमानजनक शब्द नहीं बोला है। सब कुछ विषय से जुड़ा हुआ है। और यह विषय आपके कार्यालय में जाने के बाद ही उन्हें बोलने की अनुमति दी गई थी।'' सदस्य पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए खरगे ने कहा, ''सदन के नेता हस्तक्षेप कर यह नहीं कह सकते कि जो भी कहा गया है वह अपमानजनक है और उसे हटाया जाए, नेता (सदन के) दबाव डाल रहे हैं। आप संसदीय लोकतंत्र के अनुसार नहीं चलना चाहते।'' सभापति ने कहा कि कार्यवाही नियमों के अनुसार चल रही है।

मोबाइल में संचार साथी ऐप अनिवार्य नहीं, आदेश वापस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को देश में बिकने वाले स्मार्टफोन्स में संचार साथी साइबर सुरक्षा ऐप को पहले से इंस्टॉल करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। यह फैसला संसद में ऐप से जुड़ी गोपनीयता संबंधी चिंताओं पर चल रही बहस के बीच आया है। इससे पहले एक सरकारी आदेश में फोन निर्माताओं को अपने डिवाइस में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने और पुराने फोन को अपडेट करने का आदेश दिया गया था कई विपक्षी सदस्यों ने इस कदम की आलोचना की है और कहा है कि इससे सरकारी निगरानी और व्यक्तिगत संचार में घुसपैठ की संभावना बढ़ जाएगी। सरकार के अनुसार, यह ऐप केवल उपयोगकर्ताओं को साइबर धोखाधड़ी से बचाने, दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की रिपोर्ट करने में उनकी सहायता करने और साइबर अपराध से निपटने में सार्वजनिक भागीदारी या जनभागीदारी को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। बयान के अनुसार सिर्फ पिछले एक दिन में, छह लाख नागरिकों ने ऐप डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण कराया है। यह इसके उपयोग में 10 गुना वृद्धि है। संचार साथी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, सरकार ने मोबाइल विनिर्माताओं के लिए इसे पहले से 'इंस्टॉल' करना अनिवार्य नहीं करने का फैसला किया है। दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर को आदेश में, स्मार्टफोन विनिर्माताओं को सभी नए मोबाइल फोन में ऐप को पहले से लगाने और पुराने मोबाइल फोन में इसे अद्यतन करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेताओं ने इससे जासूसी की चिंता जताई। उनका कहना है कि यह ऐप कॉल सुन सकता है और संदेशों की निगरानी कर सकता है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: पीएम ने सांसदों को दिया मोदी मंत्र; कहा- जीतना है, ममता सरकार को काउंटर करें

कोलकाता।

2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहला चुनाव असम में होगा। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं, केरल में 140, तमिलनाडु में 234, पश्चिम बंगाल में 294 और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों को साफ संदेश देते हुए कहा है कि वे तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखें और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री ने सांसदों को राज्य की स्थिति पर आक्रामक रुख अपनाने और लोकतंत्र को बचाने के नाम पर जनता के बीच और मजबूती से उतरने को कहा। नई दिल्ली में बुधवार को पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बैठक में मालदा उत्तर से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू भी मौजूद रहे, जिन पर अक्टूबर में भीड़ ने हमला किया था। प्रधानमंत्री ने उनकी कुशलक्षेम पूछी और बाकी सांसदों से कहा कि उन्हें राज्य की तृणमूल सरकार का मजबूती से मुकाबला करना होगा ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाया जा सके। भाजपा नेताओं के अनुसार, मोदी ने साफ कहा कि चुनाव जीतना है और जीतेंगे। बैठक के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पार्टी नेताओं को कहा कि राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाए और जनता के बीच लगातार पहुंच बनाकर रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पार्टी को पूरी ताकत झोंकने के निर्देश दिए हैं ताकि अगले साल टीएमसी सरकार को सत्ता से बाहर किया जा सके।

मजूमदार ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई को और तेज करेगी।

***जनसंपर्क और ज़मीनी विरोध पर ज़ोर**
***पीएम मोदी ने बंगाल बीजेपी सांसदों को दिया चुनावी सफलता का सीक्रेट फॉर्मूला**

काम और समर्पण की सराहना

दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्पण और जनता के बीच उनकी सक्रियता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मोदी ने कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा के साथ जनसंपर्क अभियान चलाने और प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। बिस्ता के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़े रहे हैं और यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है।

बंगाल में चुनावी रणनीति तेज

भाजपा पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में पूरी तरह जुट चुकी है। बिहार में भाजपा-जदयू गठबंधन की बड़ी जीत के बाद पार्टी का उत्साह बढ़ा है और केंद्र नेतृत्व चाहता है कि उसका असर बंगाल में भी दिखे। बैठक को इसी रणनीतिक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें सांसदों को चुनावी माहौल और टीएमसी सरकार के खिलाफ मजबूत अभियान चलाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

धनबाद के 5 इलाकों में गैस रिसाव, 2 दर्जन बीमार; 1 हजार लोगों पर असर

धनबाद। केंदुआ में बुधवार को जमीनी गैस रिसाव होने के कारण पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस गैस रिसाव से करीब एक हजार से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है और दो दर्जन से अधिक लोग बीमार हुए हैं। इन सभी को आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बीसीसीएल की कोयला परियोजना इलाके में घटना घटी है। सूचना मिलने के बाद बीसीसीएल की सेफ्टी टीम पहुंची और जांच शुरू कर दिया है। हालांकि गैस को लेकर बीसीसीएल की ओर से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस भी कैंप कर रही है। वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए आधा दर्जन से अधिक एंबुलेंस को तैनात किया गया है। गैस रिसाव केंदुआडीह थाना के पीछे का इलाका समेत राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला, पांच नंबर समेत अन्य आसपास के क्षेत्र में हुआ। धरती फटी और उसमें से गैस निकलने लगा।

न योजना, न चर्चा, न संवाद: राहुल गांधी का आरोप, मोदी सरकार बहुजनों से कर रही विश्वासघात

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को जाति जनगणना के संबंध में संसद में कोई रूपरेखा या चर्चा न होने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बहुजनों के साथ विश्वासघात किया है। राहुल गांधी ने संसद में उनसे पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर साझा किया और आरोप लगाया कि केंद्र जाति जनगणना कराने की कोई इच्छा नहीं रखता है। गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना के बारे में एक प्रश्न पूछा - उनका जवाब चौंकाने वाला है। कोई ठोस रूपरेखा नहीं, कोई समयबद्ध योजना नहीं, संसद में कोई चर्चा नहीं और जनता से कोई संवाद नहीं। अन्य राज्यों में सफल जाति जनगणना की रणनीतियों से सीखने की भी कोई इच्छा नहीं है। जाति जनगणना पर मोदी सरकार का यह रुख देश के बहुजनों के साथ विश्वासघात है। राहुल गांधी ने दशवार्षिक जनगणना की तैयारी के लिए प्रमुख प्रक्रियात्मक चरणों का विवरण और संभावित समय-सीमा, जिसमें प्रश्न तैयार करना और समय-सारिणी शामिल है, के बारे में पूछा है; क्या सरकार जनगणना के प्रश्नों का मसौदा प्रकाशित करने और इन प्रश्नों पर जनता या जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेने का प्रस्ताव रखती है; और क्या सरकार विभिन्न राज्यों में किए गए जाति सर्वेक्षणों सहित पिछले अनुभवों पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? जाति जनगणना पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, केंद्र ने उत्तर दिया कि अगली जनगणना पिछली जनगणनाओं से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखेगी और संबंधित हितधारकों से सुझाव मांगेगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के उत्तर में कहा गया है, जनगणना का इतिहास 150 वर्षों से अधिक पुराना है। अगली जनगणना पिछली जनगणनाओं से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखेगी। प्रत्येक जनगणना से पहले, संबंधित हितधारकों से सुझाव भी मांगे जाते हैं।

मोदी सरकार मजदूर विरोधी, श्रम संहिता से रोजगार की सुरक्षा को खतरा : खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को मोदी सरकार पर ''मजदूर विरोधी और पूंजीपति समर्थक होने का आरोप लगाया और दावा किया कि हाल ही में लागू चार श्रम संहिताओं के कारण श्रमिकों के रोजगार की सुरक्षा एवं स्थायित्व खतरे में पड़ गया है। खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी सांसदों ने श्रम संहिताओं के खिलाफ बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया।

बाद में खरगे ने 'एक्स पर पोस्ट किया, ''मोदी सरकार मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी और पूंजीपतियों की समर्थक है। विपक्षी दलों ने आज संसद में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए, नयी लागू की गई श्रम संहिताओं पर कड़ी आपत्ति जताई। नयी संहिताओं में कुछ गंभीर चिंताएं हैं। उन्होंने दावा किया कि छंटनी की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिकों तक कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि भारत में 80 प्रतिशत से अधिक कारखाने अब सरकार की मंजूरी के बिना श्रमिकों को नौकरी से हटा सकते हैं, जिससे नौकरी की सुरक्षा कम हो जाएगी। खरगे ने कहा कि तय समयसीमा वाले रोजगार के विस्तार से कई स्थायी नौकरियां खत्म हो जाएंगी तथा कंपनियां अब दीर्घकालिक लाभ से बचते हुए, अल्पकालिक अनुबंध पर श्रमिकों को काम पर रख सकती हैं। उनका कहना है, ''संहिता के तहत कागज पर आठ घंटे काम की बात की गई है, लेकिन 12 घंटे की शिफ्ट भी कराई जा सकती है.... इससे थकान और सुरक्षा जोखिम बढ़ जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''संहिता प्रवासियों के लिए सुरक्षा उपायों का विस्तार करने, विस्थापन भत्ते को हटाने और प्रतिबंधात्मक 18,000 रुपये की आय सीमा को बनाए रखने में विफल है, जिससे कई प्रवासियों को सुरक्षा के बिना छोड़ दिया गया है। अनिवार्य आधार-आधारित पंजीकरण से प्रवासियों और अनौपचारिक श्रमिकों के बाहर होने का जोखिम है, जिन्हें अक्सर दस्तावेजीकरण त्रुटियों या सीमित डिजिटल पहुंच का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से इससे सामाजिक-सुरक्षा नामांकन में बाधाएं पैदा होती हैं। केंद्र ने बीते 21 नवंबर को 2020 से लंबित चार श्रम संहिताओं को लागू कर दिया, जिनमें सभी के लिए समय पर न्यूनतम वेतन और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा जैसे श्रमिक-अनुकूल उपायों को शामिल किया गया है।

बीजापुर में 6 माओवादी मारे गए, 2 जवान भी शहीद, मुठभेड़ जारी

बीजापुर।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुई एक मुठभेड़ में कम से कम छह नक्सली मारे गए। दुर्भाग्य से, नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के दो जवान शहीद हो गए। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा-बीजापुर सीमा के पास गंगालूर के जंगली इलाके में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड , स्पेशल टास्क फोर्स और कोबरा (CRPF की एक विशिष्ट इकाई, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन) की एक संयुक्त टीम इस अभियान को अंजाम दे रही थी। दंतेवाड़ा के डीआईजी कमलोचन कश्यप ने बताया कि पिछले दो घंटों से मुठभेड़ जारी है। उन्होंने कहा कि अब तक छह माओवादी मारे गए हैं और उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में दो हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जवानों ने बड़ी संख्या में नक्सलियों को घेर लिया है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। इस नवीनतम कार्रवाई के साथ, इस वर्ष अब तक छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ों में 268 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 239 बस्तर संभाग में, जिसमें बीजापुर और दंतेवाड़ा सहित सात जिले शामिल हैं, मारे गए, जबकि 27 अन्य रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में मारे गए। दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में दो नक्सली मारे गए।

हरियाणा की साइको किलर लेडी: मासूम बच्ची को तड़पा-तड़पा कर मारा; अपने बेटे समेत चार बच्चों का कर चुकी है कत्ल

पानीपत। पानीपत में छह साल की बच्ची की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने साइको किलर महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने पानी के टब में डुबोकर मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, महिला पहले भी खुद के बेटे समेत चार बच्चों की निर्मम हत्या कर चुकी है। बता दें कि इसराना क्षेत्र में नौल्था गांव में हुई छह साल की बच्ची की हत्या महिला ने की थी। साल 2023 में आरोपी महिला ने अपने ननद की बेटी और खुद के बेटे की हत्या की थी। वहीं, महिला ने अगस्त 2025 में सिवाह गांव में भी एक बच्ची को मौत के घाट उतारा था। आरोपी महिला का नाम पूनम बताया जा रहा है। आरोपी महिला सोनीपत के भावड़ गांव की रहने वाली है और उसके पति का नाम नवीन है।

इसराना थाना क्षेत्र के नौल्था गांव में पानी के टब में डूबने से हुई बच्ची विधि (6) की मौत हुई थी। बच्ची के दादा सेवानिवृत्त एसआई पाल सिंह ने पानी में डुबोकर बच्ची की हत्या करने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने मृतक बच्ची के दादा की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने बीते रोज मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया था। सोनीपत के भावड़ गांव निवासी पाल सिंह ने बताया कि उनका परिवार सोनीपत के रामनगर में रहता है। उनके रिश्तेदार नौल्था गांव निवासी सतपाल के बेटे अमन की शादी थी। बीते सोमवार को उसकी बारात गई थी। जिसमें शामिल होने के लिए वह अपनी पत्नी ओमवती, बेटे संदीप, पुत्रवधू, पोती विधि और 10 माह के पौत्र के साथ शामिल होने के लिए आए थे। सोमवार को करीब डेढ़ बजे बारात नौल्था गांव से रवाना हुई थी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने होम डिपार्टमेंट के डैशबोर्ड को किया लॉन्च

चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज गृह विभाग के डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। यह एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरे राज्य में कानून लागू करने, इमरजेंसी में मदद करने और पब्लिक सेफ्टी मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव लाएगा। इस पहल को एक अहम मील का पत्थर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए सिस्टम से सीनियर अधिकारी एक ही इंटरफेस पर पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, जेल और दूसरे जरूरी विंग से रियल-टाइम जानकारी पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे गृह विभाग में समन्वय बेहतर होगा, क्षमता बढ़ेगी और तेज़ी से फैसले लेने में मदद मिलेगी। श्री नायब सिंह सैनी ने इस नई पहल के लिए होम सेक्रेटरी और दूसरे सीनियर अधिकारियों और टेक्निकल टीम को बधाई दी। यह इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस), डायल-112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ई-प्रिजन, ई-चालान, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और इससे जुड़े प्लेटफॉर्म जैसे जरूरी सिस्टम को एक साथ लाता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डैशबोर्ड के साथ ई-समन और ई-चालान को जोड़ने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने डैशबोर्ड के जरिए हरियाणा की सभी 20 जेलों की रियल टाइम में लाइव मॉनिटरिंग की तारीफ की। इससे अधिकारी कैदियों के ट्रांसफर, एक्सपेंशन की जरूरतों और भीड़ कम करने के उपायों की प्लानिंग कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की रियल-टाइम विज़िबिलिटी से ज्यादा जानकारी और समय पर प्रशासनिक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। बैठक में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि 1 जुलाई, 2024 से 30 नवंबर, 2025 के बीच डैशबोर्ड पर 1,78,038 एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें से 1,32,790 केस निपटाए जा चुके हैं, जो 74.58 प्रतिशत डिस्पोज़ल रेट दिखाता है। इमरजेंसी में, पुलिस अब एवरेज 11 मिनट 54 सेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम देती है और डिस्पैच 7 मिनट 36 सेकंड के अंदर हो जाता है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सर्विस औसतन 23 मिनट 49 सेकंड में लोगों तक पहुंच रही है, जिससे उन्हें जल्दी मेडिकल मदद मिल रही है और नतीजे बेहतर हो रहे हैं। डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि डैशबोर्ड को जल्द ही गृह विभाग और न्याय प्रशासन से भी जोड़ा जाएगा।

पुलिस, प्रॉसिक्यूशन, ज्यूडिशियरी, जेल और फॉरेंसिक के बीच बिना रुकावट डेटा फ्लो को मुमकिन बनाने के लिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) को इंटीग्रेट करने का भी प्लान चल रहा है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म पुलिस स्टेशनों की परफॉर्मेंस-बेस्ड रैंकिंग को आसान बनाएगा, अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करेगा और लगातार सुधार को बढ़ावा देगा। यह सभी 24 पुलिस जिला और 413 पुलिस स्टेशनों के रियल-टाइम डेटा से भी चलेगा। डैशबोर्ड का मकसद पूरे राज्य में क्राइम ट्रेंड्स पर नज़र रखने, विभाग के बीच तालमेल सुधारने और पब्लिक सेफ्टी बढ़ाने के लिए एक बड़े निर्णय-समर्थन प्रणाली के तौर पर काम करना होगा।

इस पहल को एक अहम मील का पत्थर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए सिस्टम से सीनियर अधिकारी एक ही इंटरफ़ेस पर पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, जेल और दूसरे ज़रूरी विंग से रियल-टाइम जानकारी पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे गृह विभाग में समन्वय बेहतर होगा, क्षमता बढ़ेगी और तेज़ी से फैसले लेने में मदद मिलेगी। श्री नायब सिंह सैनी ने इस नई पहल के लिए होम सेक्रेटरी और दूसरे सीनियर अधिकारियों और टेक्निकल टीम को बधाई दी।

चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वक्फ वाला दांव, कहा- किसी की जमीन छूने नहीं दूंगी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि यह कानून केंद्र लाया है और उनकी सरकार किसी भी हाल में लोगों की संपत्ति को छूने नहीं देगी। मालदा में सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए ममता ने इसे धर्म के नाम पर राजनीति कराने की कोशिश बताया और साफ कहा कि वह धर्म आधारित राजनीति नहीं करतीं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कुछ सांप्रदायिक ताकतें धर्म के नाम पर समाज में दरार डालने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून भाजपा लेकर आई है और उनकी सरकार ने न केवल विधानसभा में इसका विरोध कर प्रस्ताव पारित किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी गई। ममता ने जनता को आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी की जमीन या संपत्ति पर कोई हाथ नहीं डाल सकता और राज्य सरकार किसी भी तरह के धार्मिक टकराव को बढ़ावा नहीं देगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब

राज्य की स्थिति वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर विवाद में आ गई है। हाल ही में राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को केंद्र की यूएमआईडी पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का डेटा अपलोड करने को कहा, जिससे नए सिरे से असहज स्थिति पैदा हो गई है। इस कदम को कई लोगों ने कानून को व्यवहारिक स्वीकृति बताया है। केंद्र ने 82 हजार से अधिक वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण 6 दिसंबर तक ऑनलाइन अपलोड करने की समय-सीमा तय की है।

राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और जमीअत उलेमा-ए-हिंद बंगाल अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि अगर वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की कोशिश हुई तो मुस्लिम समुदाय चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि गांवों में जाकर कौन लोगों को बताएगा कि उनकी जमीन अब उनकी नहीं रही। चौधरी ने कहा कि समुदाय लंबे संघर्ष के लिए तैयार है और हालात को गंभीरता से देख रहा है। टीएमसी के भीतर यह असहजता अगले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए चुनौती बन गई है। स्थिति को और जटिल बनाते हुए, एआईएमआईएम कोलकाता में राज्य सरकार के इस यू-टर्न के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी में है। महीनों तक विरोध करने के बाद अब केंद्र की शर्तें मान लेने से अल्पसंख्यक राजनीति में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है।